International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA)
Multidisciplinary Peer-Reviewed Online Open Access Journal Impact Factor: 5.466
Volume 4, Issue 3, July-Sep 2024 ID: IJCRTA0000126 ISSN: 2583-1801
Email: ijcrta@gmail.com Website: www.ijcrta.org

एक राष्ट्र एक अंशदान: एक विहंगावलोकन

One Nation One Subscription: An Overview

डॉ.गौतम सोनी,

उप पुस्तकालयाध्यक्ष,

डॉ. भगवानदास केन्द्रीय पुस्तकालय,

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

ईमेल: drgautamsoni.mgkvp@gmail.com

लेख संदर्भ: सोनी, गौतम. (२०२४). एक राष्ट्र एक अंशदान: एक विहंगावलोकन. International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583-1801, 4 (3), pg. 12-15. ijcrta.org

(यह लेख एक राष्ट्र एक अंशदान की अवधारणा को व्यक्त करता है, ओएनओएस नीति वास्तव में यह भी बताती है कि कैसे ओएनओएस क्रियान्वित करके पत्र पत्रिकाओं के अंशदान के खर्च को कम करने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर सकती है)

एक राष्ट्र एक अंशदान (ONOS) भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक योजना है। जिसमें सरकार पत्रिका प्रकाशकों के साथ एकल अंशदान भुगतान के तहत भारत में सभी लोगों की पहुँच पत्र–पत्रिकाओं के लेखों तक बनाने के लिए विमर्श करेगी। भारत के शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अन्य संस्थानों के प्रमुखों को लिखे एक पत्र में कहा था, कि भारत अप्रैल 2023 से वैज्ञानिक शोध पत्रों और अकादमिक पत्रिकाओं के लिए एक राष्ट्र एक अंशदान (ओएनओएस) नीति अपनाएगा, ताकि देश भर में शोधकर्ताओं की पहुंच शोध पत्रों तक सुनिश्चित की जा सके। यह नीति व्यक्तिगत एवं संस्थागत अकादमिक पत्रिकाओं की महंगी सदस्यताओं को प्रतिस्थापित करेगी, हालाँकि कई कारणों से यह नीति अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है। मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव के. संजय मूर्ति ने कहा कि एक राष्ट्र एक अंशदान (ओएनओएस) लागत–वार्ता समिति शीघ्र ही प्रकाशकों के साथ बातचीत शुरू करे और केंद्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों से 70 प्रकाशकों के ई–संसाधनों के नवीनीकरण को अस्थायी रूप से रोकने का आग्रह करे, जब तक कि बातचीत चल रही है। मूर्ति ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि ई–संसाधनों का नवीनीकरण ओएनओएस गतिविधियों और वार्ताओं के साथ तालमेल बिठाए। सरकार ने 2020 के अंत में एक राष्ट्र एक अंशदान (ओएनओएस) योजना का प्रस्ताव रखा, इसे पांचवें राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के मसौदे के हिस्से के रूप में घोषित किया, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं रखी गई। भारत के विज्ञान एवं प्रौधोगिकी की राष्ट्रीय अकादमियों ने एक रिपोर्ट में कहा था कि यह क्षेत्र एक वर्ष में लगभग INR15 बिलियन (US $ 184 मिलियन) पत्रिका अंशदान (Journal Subscription) पर खर्च करता है।

सरकार एवं पत्रिका प्रकाशकों के मध्य लम्बे विमर्श अन्तराल का प्रभाव

हालाँकि, शिक्षाविदों के अनुसार भारत में प्रकाशकों की बड़ी संख्या को देखते हुए, पत्रिका प्रकाशकों से भुगतान पर केंद्रीय विमर्श करना आसान नहीं है, और पत्रिका अंशदान (Journal Subscription) को अस्थायी रोकना एक जोखिम भरी रणनीति हो सकती है। शिक्षाविदों ने कहा कि अगर बातचीत लंबी होती है या रुक जाती है, तो शोधकर्ताओं को पत्र–पत्रिकाओं एवं शोध पत्रों के अभिगम से वंचित करने के दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते है।

उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि ओएनओएस को पेशेवर वार्ताकारों की सेवाएं लेनी चाहिए, और न केवल सदस्यता की दरों बल्कि सदस्यता के नियमों और शर्तों और कानूनी मुद्दों पर भी बातचीत करनी चाहिए"। मिस्र जैसे देश पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के समझौते कर चुके हैं। कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी उच्च

शिक्षा प्रणालियों में से एक और पर्याप्त शोध परिणामों के साथ, भारत अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ इस तरह के समझौते करने वाला सबसे बड़ा देश होगा।

सफल समझौते के संभावित लाभ

इस कदम से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संगठनों सहित सभी शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ–साथ देश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होने की आशा है। यदि विमर्श सफल रहा तो भारतीय संस्थानों में लोगों की वैज्ञानिक ज्ञान तक निर्बाध पहुंच हो सकेगी और इसका अर्थ यह होगा कि छोटे संस्थान या कम संसाधनों वाले संस्थानों को पत्रिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच आसान होगी एवं संसाधनों तक बेहतर पहुंच से शोधकर्ता की उत्पादकता और गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

पायल बी जोशी, शोधकर्ता और शेफाली रिसर्च लेबोरेटरीज की प्रमुख ने कहा, यह भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक साहसिक और सकारात्मक कदम है जो मुक्त अभिगम (Open Access) प्रकाशनों के लिए अपने समर्थन को दर्शाता है।

यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज के अनुसार इस मॉडल के प्रमुख लाभार्थी सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, संस्थान और स्वतंत्र शोधकर्ता होंगे। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से उच्च सदस्यता दरों पर छूट की बातचीत करना एक बड़ी चुनौती है।

यदि सरकार पत्रिकाओं की दरों पर बातचीत करने और अपने पुस्तकालय भंडारों में सुधार करने में सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में शोधकर्ताओं के लिए शीर्ष स्तरीय पत्रिकाओं तक पहुंचना और अपने शोध प्रकाशित कराना आसान हो जाएगा। इस मॉडल को बनाए रखने का लिटमस टेस्ट तब होगा जब प्रकाशक पत्रिकाओं की सदस्यता दरों को संशोधित करेंगे।

प्रकाशक भी दबाव में हैं?

कठिन और खतरनाक स्थितियों से निपटने पर केंद्रित एक शोध समूह, दिल्ली स्थित हजार्ड्स सेंटर के संस्थापक दुनू रॉय ने कहा प्रकाशक इसके लिए सहमत होंगे या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है क्योंकि प्रकाशक भी दबाव में हैं। कई प्रकाशकों के लिए, सबसे बड़े ग्राहकों में से एक सरकारी संस्थान हैं इसलिए वे इस मामले में बहुत सावधान रहेंगे। रॉय ने यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज को बताया कि अगर सरकार के साथ समझौता होने तक अंशदान (Subscription) रोक दिया जाता है, तो प्रकाशनों तक अवैध पहुंच (अभिगम) किसी न किसी रूप में जारी रहेगी। प्रकाशक अवैध अभिगम को नहीं रोक सकते। अवैध प्रकाशक इसे प्रिंट, पुनर्मुद्रित और इंटरनेट पर डालने लगेंगे। संपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर प्रतिबंध के स्तर के साथ, उन प्रतिबंधों को उपमार्ग (Bypass) करने, कम करने और पार करने के प्रयास तीव्रतम हो जाते है। कुछ समूहों को भय है कि सरकार नियमों और शर्तों से सहमति के लिए प्रकाशकों पर दबाव बनाने के लिए पत्रिकाओं के अभिगम पर प्रतिबंध लगा सकती है। जिस क्षण आप प्रतिबंध लगाते हैं और किसी विशेष वस्तु की मांग होती है, बाजार मांग की आपूर्ति के तरीके खोज लेता है। वास्तव में पूरी वैचारिक नींव यह है, कि आप बाजार खोलेंगे और साथ ही साथ बाजार को विनियमित करने में सक्षम होंगे? यह बहुत ही विरोधाभासी है, जिसे राजनीतिक रूप से हल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशकों के एक समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कॉपीराइट उल्लंघन का एक मुकदमा दायर किया, जो शोध पत्रों के छदम (Pirated) संस्करणों तक पहुंच प्रदान करने वाली एक वेबसाइट है। यह वेबसाइट भारत में अधिक लोकप्रिय है, क्यों कि कुछ शोध पत्रों एवं पत्रिकाओं की महंगी सदस्यताएँ केवल कुछ उच्च शिक्षण संस्थान ही वहन कर सकते हैं।

एल्सेवियर ने उस समय कहा था कि, ष्एल्सेवियर पूरे भारत में अनुसंधान की पहुंच बढ़ाने के भारत सरकार के उद्देश्य का स्वागत करता है और हम यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि हम आने वाले हफ्तों और महीनों में इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं।

प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु

• सरकार ने सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सभी शोधों के परिणामों और उनके द्वारा सृजित सूचनाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए एक ओपन साइंस पॉलिसी का प्रस्ताव किया है।

• सरकार ने उल्लेखनीय रूप से दुनिया भर में अधिकांश महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिकाओं को खरीदने और सभी भारतीयों को मुफ्त में प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

• वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए एक राष्ट्र एक अंशदान नीति वैज्ञानिक समुदाय और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है।

• दुनिया की उत्कृष्ट पत्रिकाएँ इतनी महंगी हैं कि शीर्ष संस्थान भी इन पत्रिकाओं की सदस्यता लेने में चयनात्मक हैं।

• 3000 से 4000 उच्च प्रभाव वाली (Impact Factor) पत्रिकाओं को खरीदने का प्रस्ताव किया गया है और इन पत्रिकाओं की सदस्यता के लिए 2000 करोड़ से 3000 करोड़ के अनुमानित बजट की योजना बनाई गई है।

• सृजित सभी प्रकार के आकडों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला में संग्रहित किया जाएगा।

• यह वेधशाला 'FAIR' (फेयर, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल और रियूजेबल) के माध्यम से सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान को डेटा प्रदान करेगी।

• गोपनीयता संबंधी मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा, या बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में उपयुक्त रूप से अज्ञात और संपादित डेटा को सुलभ बनाया जाएगा।

• मसौदा नीति में भारतीय पत्रिकाओं के स्तर में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने का भी प्रस्ताव है। यह फर्जी पत्रिकाओं के प्रकाशन पर भी गंभीर रोक लगाएगा।

• यह अनुमान लगाया गया है कि इस नीति के माध्यम से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

• उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस नीति को पारित कर देगी।

• यह 2013 की एसटीआई नीति का स्थान लेगी।

• प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास, साथ ही प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण इस नीति में नियोजित दोतरफा दृष्टिकोण है।

• उचित बुनियादी ढाँचे के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को मजबूत किया जाएगा ताकि रेलवे, रक्षा, घरेलू उपकरणों आदि जैसे क्षेत्रों में आयात को कम किया जा सके।

• एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

• नीति के मसौदे में सामरिक प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है जो सभी रणनीतिक सरकारी विभागों को जोड़ेगा और खरीदे जाने या स्वदेशी रूप से निर्मित प्रौद्योगिकियों पर नजर रखेगा और प्रस्तावित करेगा।

निष्कर्ष

वास्तव में एक राष्ट्र एक अंशदान (ONOS) योजना यदि मूर्त रूप लेती हैं तो शोध एवं सन्दर्भ के क्षेत्र में शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों के लिये एक अभूतपूर्व कदम साबित होगी।

सन्दर्भ सूची–

1. https://aws-static.iicdelhi.in/s3fs-public/2022-09/OP-111_Final_13.09.2022.pdf

2. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AU2865.pdf?source=pqals
3. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20221125055551605
4. https://navendu.me/posts/onos-problems/
5. https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/one-nation-one-subscription-initiative-by-education-ministry-to-allow-open-access-to-research-papers-from-april-1-2299301-2022-11-19
6. https://www.newsonair.gov.in/core-committee-formed-to-oversee-implementation-of-one-nation-one-subscription-to-facilitate-academic-and-research-development-institutions/